

प्रेषक,

सी० भास्कर,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,  
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

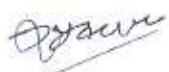
देहरादून: दिनांक: 11 सितम्बर, 2007

विषय:- दिनांक 31.03.2007 को अवशेष ऋण की धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 293/उपाकालि/उ०म०प्र०(वित्त), दिनांक 25.05.2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या REC/FIN/Loan/GoU/2006-07/02/6296-3951-52 दिनांक 19.05.2006 के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित रु० 1,62,100.00 (रु० एक लाख बासठ हजार एक सौ मात्र) के भुगतान हेतु व्यय के लिए रुपये 1000 (रु० एक हजार) सगत मद से तथा रुपये 1,62,000 (रु० एक लाख बासठ हजार मात्र) सलग्न बी.एम. 15 के कालम 5 में अंकित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यवर्तित कर आपके निर्वर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि का व्यय REC के उक्त सन्दर्भित पत्र में इंगित जनपद में कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में REC से सम्बन्धित योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृति की सूचना सम्बन्धी REC के पत्रों में इंगित सभी शर्तों की शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी। इसमें त्रुटि की दशा में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं उनके सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- परियोजना हेतु ऋण प्राप्ति के सम्बन्ध में REC के साथ किये गये अनुबन्ध में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुये कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
- ऋण एवं ब्याज की समय से वापसी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा शासन को इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि शासन द्वारा ऋण एवं ब्याज की वापसी REC को समय से की जा सके। मोरेटोरियम की अवधि में देय ब्याज का समय से भुगतान भी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा शासन को उक्तानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा भुगतान के विवरण साक्ष्य सहित शासन को यथासमय उपलब्ध कराये जायेंगे और ब्याज की धनराशि संचित निधि में जमा कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा REC का ब्याज वापस किया जायेगा।
- नियत अवधि पर भुगतान/वापसी न करने पर 2.75 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दण्ड के रूप में अतिरिक्त दय होगा तथा 6 माह से अधिक भुगतान/वापसी में चूक की दशा में योजना का विशेष स्वरूप समाप्त हो जायेगा, जिस दशा में ऋण पर सामान्य ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय प्रचलित) लगेगा। अतः उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में योजना का संपादन/कियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार समय से करते हुये नियत तिथि तक किश्त व ब्याज की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- योजना में इस किश्त आहरण के बाद यदि कोई अगला प्रतिपूर्ति दावा नियत अवधि में REC को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो किश्त में अवमुक्त सम्पूर्ण ऋण की राशि को ब्याज/दण्ड ब्याज सहित REC को वापस किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित समय में उपयोग कर उस धनराशि से योजनावार कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा, ताकि आगामी किश्त प्राप्त होने में विलम्ब न हो।



- 9 किश्तों एवं ब्याज की वापसी नियत तिथि से पूर्व अवश्य कर दिया जाय एवं इस हेतु नोटिस/सूचना का इन्तजार् न किया जाय। धनराशि सीधे REC को भुगतान करते हुये शासन को सूचना संसमय दी जाय।
- 10 UPCL द्वारा प्रत्येक माह में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य सरकार के पक्ष में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां जैसे विद्युत ट्रेडिंग, निःशुल्क विद्युत के सापेक्ष भुगतान, विद्युत शुल्क, राज्य सरकार के सापेक्ष लम्बित ऋणों के मूलधन व ब्याज आदि का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जायेगा और इस हेतु विस्तृत विवरण भी शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 11 स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण बीजक पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार में प्रस्तुत कर किया जायेगा।
- 12 उपरोक्त आवंटित की जा रही धनराशि में से रु० 1,61,100.00 (रु० एक लाख इकसठ हजार एक सौ मात्र) को ही आहरित किया जायेगा।
- 13 स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य उपक्रमों में निवेश-04-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर०ई०सी० से ऋण-00-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।
- 2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय स०- 36/XXV11-2/2006 दिनांक 07 सितम्बर, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक- बी०एम०-15

भवदीय,

(सी० भास्कर)  
अपर सचिव

संख्या: 1138  
/1(2)/2007-06(1)/1/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
  - 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
  - 3- निजी सचिव-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञान हेतु।
  - 4- जिलाधिकारी, देहरादून।
  - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
  - 6- सहायक मुख्य लेखाधिकारी (ऋण), ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली।
  - 7- निदेशक (वित्त), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, देहरादून।
  - 8- वित्त अनुभाग-2
  - 9- ✓ प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
  - 10- कर्जा सैल।
  - 11- गार्ड फाईल हेतु।
- संलग्नक- बी०एम०-15

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)  
अनु सचिव



विभाग का नाम- ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

कल्ट प्राविधान तथा ऐश्वर्यपूर्णता का विवरण	मानक मदवार अथवा वार्य	वित्तिय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	उत्तराखण्ड सरकार के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	संशोधित जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाता है।	पुनर्विनिर्माण के बाद स्वयं की कुल धनराशि	पुनर्विनिर्माण के बाद स्वयं की कुल धनराशि	अनुदान के फलस्वरूप।
6801- वित्तिय वर्ष के लिए कर्तव्य धनराशि आयाजनागत 190-सर्वकारी क्षेत्र के उपक्रम और अन्य उपक्रमों में निवेश 03-उत्तराखण्ड राज्य के उपक्रम और अन्य उपक्रमों में निवेश 30-निवेश, ऋण	2	170000	146739	5. 6801- वित्तिय वर्ष के लिए कर्तव्य धनराशि आयाजनागत 190-सर्वकारी क्षेत्र के उपक्रम और अन्य उपक्रमों में निवेश 03-उत्तराखण्ड राज्य के उपक्रम और अन्य उपक्रमों में निवेश 30-निवेश, ऋण	6	7	8. अनुदान के फलस्वरूप।
योग-	317000	170000	146739	162	163	163	अनुदान के फलस्वरूप।

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनिर्माण से बजट मैनुअल के परिच्छेद- 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित समाप्ति का एव प्रविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(सी० भास्कर)  
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-2

संख्या 341 (ख)(2) XXVI(12)2007

देहरादून दिनांक 07 सितम्बर 2007

पुनर्विनिर्माण स्वीकृत

(टी.एन. सिंह)

अपर सचिव, वित्त

सेवा में

महालेखकार

उत्तराखण्ड, देहरादून।

1138

संख्या: 112/2007-06(1)/01/04 दिनांक 11 सितम्बर 2007

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य कार्याधिकारी, देहरादून।

2- वित्त अनुभाग 2

(सी० भास्कर)

अपर सचिव